भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-166
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

आईआईटी, आईआईएम और एम्स की स्थापना

†166. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में स्थापित किए गए नए आईआईटी, आईआईएम, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन संस्थानों की स्थापना का राज्यवार वितरण क्या है;
(ग) केंद्रीय बजट 2025-26 में उच्च शिक्षा अवसंरचना विकास के लिए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है और विगत वर्षों के वास्तविक व्यय से इसकी तुलना क्या है;
(घ) नव स्थापित और मौजूदा आईआईटी और आईआईएम में संकाय की कमी और अनुसंधान निधि की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ङ) अंतर्राष्ट्रीय संकायों को आकर्षित करने के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;
(च) प्रमुख संस्थानों में बहु-विषयक अनुसंधान, स्टार्टअप इनक्यूबेशन केंद्रों और एआई-आधारित शिक्षण मॉड्यूल को बढ़ावा देने वाली नीतियों का ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच की खाई को पाटने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): वर्ष 2014 से पहले देश में 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कार्यात्मक थे। बजट घोषणा वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के अनुसरण में आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू), गोवा (आईआईटी गोवा) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छह नए आईआईटी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के अनुसरण में,

झारखंड में धनबाद स्थित भारतीय खनन विद्यालय को वर्ष 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में देश में 23 आईआईटी कार्यात्मक हैं।

वर्ष 2014 से पहले देश में 13 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) कार्यात्मक थे और वर्तमान में 21 आईआईएम हैं। पंजाब (आईआईएम अमृतसर), बिहार (आईआईएम बोधगया), ओडिशा (आईआईएम संबलपुर), जम्मू और कश्मीर (आईआईएम जम्मू), हिमाचल प्रदेश (आईआईएम सिरमौर), महाराष्ट्र (आईआईएम नागपुर) और आंध्र प्रदेश (आईआईएम विशाखापत्तनम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सात नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2023 में, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीआईई), मुंबई को आईआईएम मुंबई में परिवर्तित कर दिया गया है।

वर्ष 2014 से पहले देश में 30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और एक भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) कार्यात्मक थे और वर्तमान में एक आईआईईएसटी के अतिरिक्त 31 एनआईटी हैं। एनआईटी आंध्र प्रदेश की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी।

वर्ष 2014 से पहले देश में 9 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) कार्यात्मक थे और वर्तमान में 25 आईआईआईटी हैं। आंध्र प्रदेश (आईआईआईटीडीएम कुरनूल), हरियाणा (आईआईआईटी सोनीपत), हिमाचल प्रदेश (आईआईआईटी ऊना), पश्चिम बंगाल (आईआईआईटी कल्याणी), कर्नाटक (आईआईआईटी धारवाड़, आईआईआईटी रायचूर), मणिपुर (आईआईआईटी सेनापति), केरल (आईआईआईटी कोट्टायम), उत्तर प्रदेश (आईआईआईटी लखनऊ), झारखंड (आईआईआईटी रांची), महाराष्ट्र (आईआईआईटी पुणे, आईआईआईटी नागपुर), मध्य प्रदेश (आईआईआईटी भोपाल), गुजरात (आईआईआईटी सूरत), बिहार (आईआईआईटी भागलपुर) और त्रिपुरा (आईआईआईटी अगरतला) राज्यों में सोलह नए आईआईआईटी स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2014 से पहले देश में 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और एक भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) कार्यात्मक थे और वर्तमान में एक आईआईएससी के अतिरिक्त सात आईआईएसईआर हैं। आंध्र प्रदेश (आईआईएसईआर तिरुपति) और ओडिशा (आईआईएसईआर बरहामपुर) में दो नए आईआईएसईआर स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2014 से पहले देश में 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) कार्यात्मक थे और वर्तमान में 48 सीयू हैं। बिहार (महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, बिहार), आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश), तेलंगाना (सम्मक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना), दिल्ली (केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली), लद्दाख (सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आठ सीयू स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2014 से पहले देश में 7 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) कार्यात्मक थे तथा वर्ष 2014 के बाद 16 एम्स की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया गया, जिनमें से 12 स्थापित हो चुके हैं तथा 4 निर्माणाधीन हैं। 12 नए एम्स महाराष्ट्र (एम्स नागपुर), आंध्र प्रदेश (एम्स मंगलगिरी), पश्चिम बंगाल (एम्स कल्याणी), उत्तर प्रदेश (एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली), पंजाब (एम्स

बठिंडा), असम (एम्स गुवाहाटी), हिमाचल प्रदेश (एम्स बिलासपुर), झारखंड (एम्स देवघर), तेलंगाना (एम्स बीबीनगर), जम्मू (एम्स विजयपुर), गुजरात (एम्स राजकोट) में स्थापित किए गए हैं।

(ग): स्वायत्त निकायों जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, सीयू का अवसंरचनात्मक विकास इन निकायों को "पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के बजट शीर्ष ओएच-35 के अंतर्गत किया जाता है। इन शीर्षों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट अनुमान 6490.04 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक व्यय 5811.92 करोड़ रुपये था।

(घ): शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आईआईटी और आईआईएम सहित केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (सीएचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। रिक्तियों का होना और उनको भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती हैं। आईआईटी अपने संस्थान में संकाय पदों के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए वर्ष भर विज्ञापन जारी करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया था।

(ङ) आईआईटी ने अंतर्राष्ट्रीय संकाय को आकृष्ट करने और वैश्विक शैक्षणिक जुड़ाव को सुदृढ़ करने के लिए कई उपायों जैसे कि व्यावसायिक विकास निधि, नए संकाय बीज अनुदान, संकाय अनुसंधान यात्रा पुरस्कार, युवा संकाय प्रोत्साहन फैलोशिप योजना, परिसर में आवास, चिकित्सा लाभ आदि को लागू किया है। यह मंत्रालय वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) का भी क्रियान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य देश के मौजूदा शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और उद्यमियों सहित विदेशों से प्रतिभा पूल का उपयोग करना है।

(च) और (छ): एनईपी 2020 में सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए प्रासंगिक चरणों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) आदि जैसे समकालीन विषयों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। एनईपी 2020 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, डिजिटल बाजार का विस्तार, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वृद्धि आदि जैसे तेजी से हो रहे बदलावों के कारण संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान करने के लिए अनुसंधान के सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

एनईपी 2020 का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के बीच के अंतर को कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों सहित सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। एनईपी 2020 में ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करके और वंचित समूहों को लक्षित सहायता प्रदान करके एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ), पीएम रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) और ट्रांसलेशनल रिसर्च जोन (टीआरजेड) जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा और उद्योग के बीच अंतर को कम करने के लिए बहु-विषयक अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम चला रही है। 6,000 से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ हैं, जबकि 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब और 15,000 से अधिक नवाचार परिषदें (आईआईसी) स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर की उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं। प्रमुख संस्थाओं में अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करते हैं तथा यूजीसी/एआईसीटीई सुधार इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप से जुड़ी डिग्री के माध्यम से उद्योग संबंधों को सुदृढ़ करती हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 990 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तीन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई थी। प्रमुख संस्थाएं एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अग्रणी तकनीकों पर केंद्रित एआई कौशल केंद्र भी स्थापित कर रही हैं। संकाय विकास कार्यक्रम, उन्नत डिजिटल अवसंरचना, तथा स्वयम और ओएनओएस जैसे प्लेटफॉर्म एआई-आधारित शिक्षा और वैश्विक अनुसंधान तक पहुंच को और अधिक सहायता प्रदान करते हैं।

देश में शैक्षणिक संस्थाओं को विश्व स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में उत्कृष्ट संस्थाएं **(आईओई)** योजना शुरू की गई थी। इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता, अनुसंधान में उत्कृष्टता, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और संकाय सदस्यों का उल्लेखनीय अनुपात तथा समाज के लिए मूर्त और अमूर्त योगदान आदि शामिल हैं।

सरकार गरीब, मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा सुलभ बनाने के लिए विभिन्न पहल जैसे कि एससी/एसटी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फेलोशिप, पीएम विद्यालक्ष्मी और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) जैसी योजनाओं के माध्यम से शुल्क में छूट या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण; एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण; जेईई परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एससी/एसटी के लिए परीक्षा संबंधी तैयारी हेतु कक्षाएं; स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में जेईई परीक्षा आयोजित करना आदि कर रही है।

***